

मैसर्स एस.एन.जी. रियल स्टेट प्रा.लि.
द्वारा श्री सत्यनारायण गुप्ता 707,
पेरिस पॉइंट, कलेक्ट्रेट चौराहा बनीपार्क, जयपुर

....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक द्वितीय, जयपुर

...अप्रार्थी

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री मनीष व्यास

अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा

उप-राजकीय अभिभाषक

....प्रार्थी की ओर से

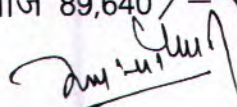
...अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 31.12.2015 प्रकरण संख्या 1021/2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक द्वितीय जयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि Lt. Col. जगदीश चन्द शर्मा व अन्य तथा प्रार्थी के मध्य एक डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट निष्पादित करने हेतु उपपंजीयक द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत किया। उपपंजीयक ने दिनांक 01.07.2013 पर पंजीबद्ध होकर सम्पत्ति की मालियत रु 5,60,19,516/- रु निर्धारित कर मुद्रांक शुल्क रु 5,60,200/- रु पंजीयन मूल्य 50,000/- रु एवं सरचार्ज रु 56,020/- वसूल प्रार्थी को लौटा दिया। तत्पश्चात् महालेखाकार जांच समिति अवधि/आंतरिक जांच अवधि 4/2013 से 3/2014 तक किये गये निरीक्षक के अनुच्छेद संख्या 1 भाग 35 में आक्षेपित कर आक्षेपानुसार मालियत 5,60,19,516/- रु के तहत कमी मुद्रांक शुल्क 8,96,307/- कमी पंजीयन शुल्क एवं सरचार्ज 89,631/- रु आक्षेपित की। राशि वसूली हेतु रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में रेफर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने ऑडिट द्वारा आक्षेपित राशि को उचित मानते हुए मूल्यांकन 5,60,19,515 कमी मुद्रांक कर 8,96,307/- कमी पंजीयन शुल्क 0/-, सरचार्ज 89,640/- रु एवं शास्ति

२३



लगातार.....2

2,95,790/- रु एवं राजस्थान वित्त विधेयक 2014 द्वारा धारा 72 में किये गये संशोधन से ब्याज की राशि देय होने से ब्याज 2,95,790/- रु कुल 15,77,530/- रु प्रार्थी से वसूल किये जाने के आदेश दिये जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थी के विरुद्ध जो वसूली का निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार कोई जांच नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। निर्णय में विवेचना एवं विश्लेषण का अभाव है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रकरण में जो शास्ति एवं ब्याज आरोपित किया है वह प्रारम्भतः शून्य है। जो प्रकरण दिनांक 01.07.2013 का समाप्त हो गया उस पर 2014 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। महालेखाकर को जांच करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उनके समक्ष कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था। डपलपमेन्ट एग्रीमेन्ट पर अधिसूचना सं. एफ. 12(11)एफडी/टैक्स/2013-115 दिनांक 06.03.2015 के अनुसार निर्धारित दर से मुद्रांक कर अदा किया गया है जिसे कन्वेन्स मानकर पुनः मुद्रांक कर वसूल नहीं किया जा सकता। इन्होंने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया।

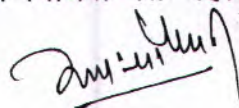
6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने तथा प्रार्थीया द्वारा धारा 5 में अंकित कारण की निर्णय की जानकारी कुर्की वारण्ट के आधार पर हुई संतोषजनक होने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ

2016



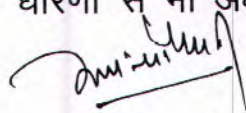
न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

sm



लगातार.....4

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2018 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

^{नत्थूराम}
(नत्थूराम)
सदस्य

^{राजीव चौधरी}
31/05/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य